# UPSC-CSE 2027/28

# DAILY CURRENT AFFAIRS

## ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**



The Indian EXPRESS

THE HINDU

pib PRESS INFORMATION BUREAU पत्र सूचना कार्यालय

23 OCTOBER

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD STAY PREPARED


“अद्भुत काम करने का केवल एक ही तरीका है— जो आप करते हैं उससे प्रेम करें।”
मदर टेरेसा
(Mother Teresa)
Small Steps Big Dreams
UPSC
IAS
PCS
Dreams
Better Study Brighter Future
Keep Going

Infrastructure

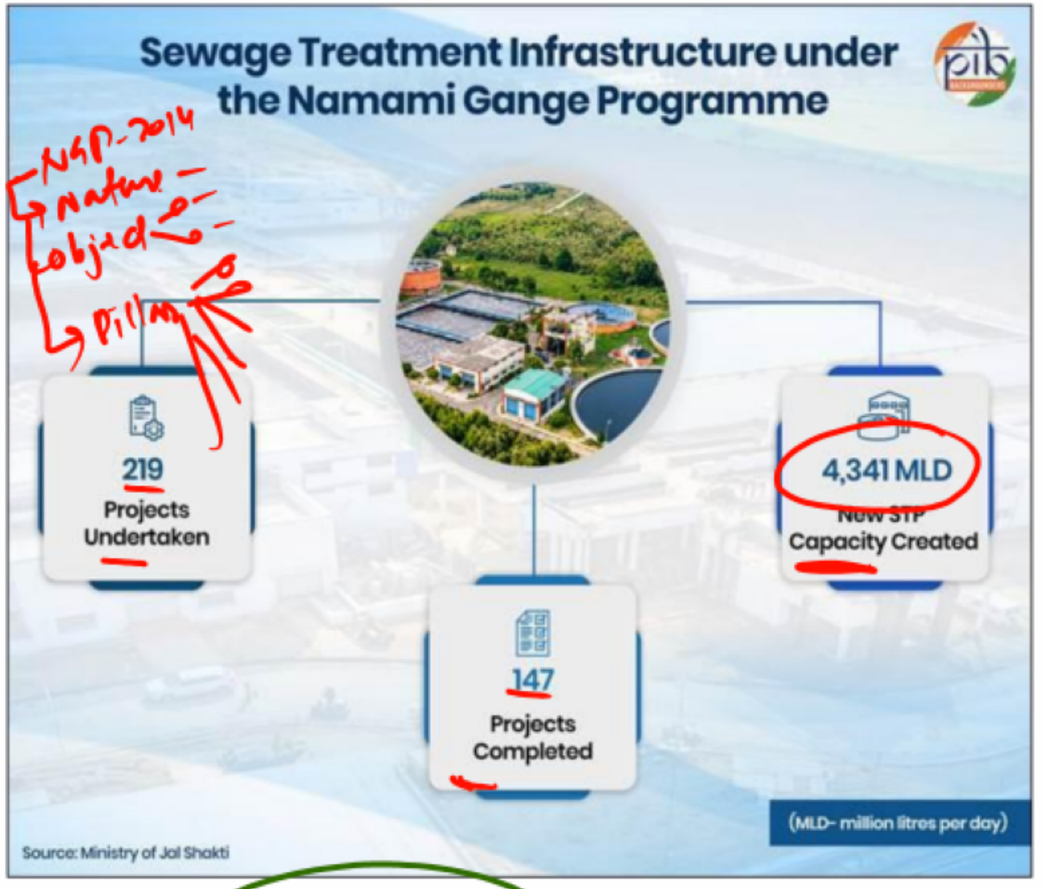
# अपशिष्ट जल उपचार का कायाकल्प

नमामि गंगे के अंतर्गत प्रौद्योगिकी और नवाचार

Posted On: 21 OCT 2026 4:16PM

घरेलू और शहरी गतिविधियों से प्रतिदिन अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। जैसे-जैसे कस्बे और शहर फैलते हैं, वैसे-वैसे सीवेज की मात्रा भी बढ़ती जाती है, जिसे इकट्ठा करने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उपचार की आवश्यकता वाले अपशिष्ट जल की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसलिए प्रभावी उपचार के लिए अपशिष्ट जल की प्रकृति, स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध अवसंरचना के आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिकी दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। शहरी इलाकों में, अपशिष्ट जल भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से केंद्रीकृत उपचार संयंत्रों तक पहुँचता है। हालांकि, जिन इलाकों में पूरा सीवर नेटवर्क नहीं है, वहां सेप्टिक टैंक और अन्य स्थानीय प्रणालियों के माध्यम से एकत्रित अपशिष्ट जल के लिए समाधान की आवश्यकता होती है। उपचार की आवश्यकताएं अपशिष्ट जल की विशेषताओं, उपलब्ध भूमि, निर्वहन मानकों और उपचारित जल के पुन: उपयोग के अवसरों के अनुसार भी भिन्न होती हैं। इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए पारंपरिक उपचार प्रणालियों और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप नवीन प्रौद्योगिकियों के संयोजन की आवश्यकता होती है।

- यह दृष्टिकोण **नमामि गंगे कार्यक्रम' (एनजीपी)** का आधार है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसके दो मुख्य उद्देश्य हैं: प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण व पुनरुद्धार करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं—सीवरेज उपचार अवसंरचना, रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट, नदी की सतह की सफाई, जैव विविधता, वृक्षारोपण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी और 'गंगा ग्राम'।
- यह कार्यक्रम प्रदूषण कम करने के अपने प्रयासों में सीवेज उपचार अवसंरचना को केंद्र में रखता है। इसमें नई उपचार क्षमता का विकास और विभिन्न उपचार प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 35,664 करोड़ रुपये की लागत वाली **219 परियोजनाएं** शुरू की गई हैं, जिनमें से **147 पूरी हो चुकी हैं**। यह गंगा बेसिन के 10 राज्यों में किए गए हस्तक्षेपों का विवरण दर्ज करता है। इनमें 6,603 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का विकास शामिल है, जिसमें से 4,341 एमएलडी क्षमता का निर्माण किया जा चुका है। इन प्रयासों से उपचार क्षमता का विस्तार होता है और साथ ही मौजूदा अवसंरचना के प्रदर्शन में भी सुधार आता है।




- सक्रिय कीचड़ से तात्पर्य उपचार प्रक्रिया में संवर्धित सूक्ष्मजीवों के समूह से है जो कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य अकार्बनिक यौगिकों में विघटित करते हैं।
- सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर एक चक्रीय सक्रिय कीचड़ उपचार प्रक्रिया है जो एकल-चरण जैविक प्रक्रिया में उच्चतम संभव उपचार दक्षता प्रदान करती है।

## फूड चेन रिएक्टर और इलेक्ट्रोकोएगुलेशन

- भारत में एनजीपी के माध्यम से **'फूड चेन रिएक्टर' (FCR)** प्रौद्योगिकी लाई गई थी। यह तकनीक 'एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस' और 'सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर' का एक बेहतर रूप है, जिसमे कृत्रिम माध्यम और पौधों की जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फायदों में कम जगह की ज़रूरत, कम बिजली की खपत और पानी से पोषक तत्वों को हटाना शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत एफसीआर पर आधारित **पाँच एसटीपी** काम कर रहे हैं: दो पश्चिम बंगाल के भाटपारा में और तीन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। बिहार के भागलपुर में भी एक ऐसा ही सयंत्र बन रहा है, जिसमें प्रति एमएलडी लगभग 175 वर्ग मीटर जगह की ज़रूरत होती है।



- इलेक्ट्रोकोएग्यूलेशन और इलेक्ट्रो-ऑक्सीडेशन. इस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई उपचार की एक और पद्धति हैं। इलेक्ट्रोकोएग्यूलेशन एक **गैर-जैविक उपचार प्रक्रिया** है, जिसमें निलंबित (सस्पेंडेड) और इमल्सीफाइड प्रदूषकों को अस्थिर करने के लिए विद्युत करंट और एक कोएगुलेंट धातु एनोड का उपयोग किया जाता है। ये प्रणालियाँ कम तापमान वाले ठंडे स्थानों, पहाड़ी इलाकों और उन जगहों के लिए उपयुक्त हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और चमोली जैसी जगहों पर ऐसी **17 प्रणालियाँ** लगाई गई हैं। इनमें पुलिस चौकी पर 0.05 एमएलडी का एसटीपी, विवेकानंद कॉलोनी में 1.19 एमएलडी का प्लांट और पोखरी बेंड में 1.25 एमएलडी का प्लांट शामिल है। इस तरह, ये प्रणालियाँ उन जगहों तक भी उपचार की अवसंरचना को पहुँचा सकती हैं, जहाँ पारंपरिक तरीकों को लागू करना मुश्किल हो सकता है।



## अपशिष्ट जल के स्रोत पर उपचार और बहुमंजिला STP (Sewage Treatment Plant)

- कार्यक्रम ने अपशिष्ट जल के स्रोत के निकट काम करने वाले उपचार समाधानों की भी खोज की है। वाराणसी के अस्सी नाले में उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया पर आधारित एक पायलट परियोजना को अतिरिक्त अपशिष्ट जल का साइट पर ही उपचार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे लंबी अवरोधन और जटिल मोड़ वाली सीवर लाइनों की आवश्यकता ही न पड़े। इस तरीके में कम से कम पक्के निर्माण (सिविल वर्क) की जरूरत होती है और काम तेजी से पूरा होता है। इसका उद्देश्य पानी की गुणवत्ता सुधारना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना और बदबू को खत्म करना है। इस मॉडल की वित्तपोषण व्यवस्था भी काफी नई और अनूठी है। इसमें शुरुआत में कोई बड़ा खर्च नहीं करना पड़ता; इसके बजाय भुगतान इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पानी साफ किया गया और काम के तय मानकों पर प्लांट कितना खरा उतरा। यह व्यवस्था उपचार प्रदर्शन के साथ पारिश्रमिक को जोड़ती है, साथ ही सयंत्र के डिजाइन और विन्यास में स्वतंत्रता भी प्रदान करती है।

## प्रकृति-आधारित और विकेंद्रीकृत उपचार समाधान

- हर बस्ती को एक ही स्तर के सीवरेज बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी बस्तियों में, पारंपरिक नेटवर्क और सीवेज उपचार सयंत्र महंगे हो सकते हैं, जबकि जगह की कमी अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करती है। एनजीपी के तहत, विकेंद्रीकृत और प्रकृति-आधारित समाधान ऐसी जगहों के लिए उपयुक्त विकल्प प्रदान करते हैं। **कृत्रिम आर्द्रभूमि (सीडब्ल्यू)** ऐसे इंजीनियर सिस्टम हैं, जो नियंत्रित परिस्थितियों में प्रदूषकों को हटाने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। एक सीडब्ल्यू सिस्टम में पानी, पौधे, सब्सट्रेट, मिट्टी और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं।



- **जोकासो** सीवेज उपचार के लिए एक और विकेंद्रीकृत विकल्प प्रदान करता है। यह एक पैकेज्ड उपचार सुविधा है, जो घरेलू सीवेज को आवश्यक नियामक मानकों और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के नियमों के अनुसार उपचारित करने में सक्षम है। इस प्रणाली में कई सीवेज-उपचार प्रक्रियाओं को एक पहले से तैयार, 'प्लग-एंड-प्ले' इकाई में शामिल किया गया है। जोकासो-आधारित विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार सयंत्र उन जगहों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जहाँ सीवेज का बहाव कम हो, जहाँ निर्माण कार्य करना कठिन हो या जहाँ जगह सीमित हो। इसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहाँ सिस्टम को ज़मीन के नीचे  लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में कई जगहों पर इस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ अब तक इसके छह सयंत्र लगाए जा चुके हैं।

## नेरेडा: कुशल जैविक उपचार

- नेरेडा, एनजीपी के माध्यम से शुरू की गई एक और जैविक अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी है, जिसमें 'एरोबिक ग्रैनुलर स्लज' (वायवीय दानेदार कीचड़) का उपयोग किया जाता है। इसमें पारंपरिक 'एक्टिवेटेड स्लज' प्रक्रिया वाले बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया सघन 'एरोबिक ग्रैन्यूल्स' (वायवीय दाने) बनाते हैं, जो आसानी से नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रौद्योगिकी के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, निर्माण लागत कम आती है और परिचालन खर्च भी कम होता है। 'एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस' की तुलना में इसमें लगभग **50%** और 'सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर' (एसबीआर) की तुलना में लगभग **20%** बिजली की बचत होती है।



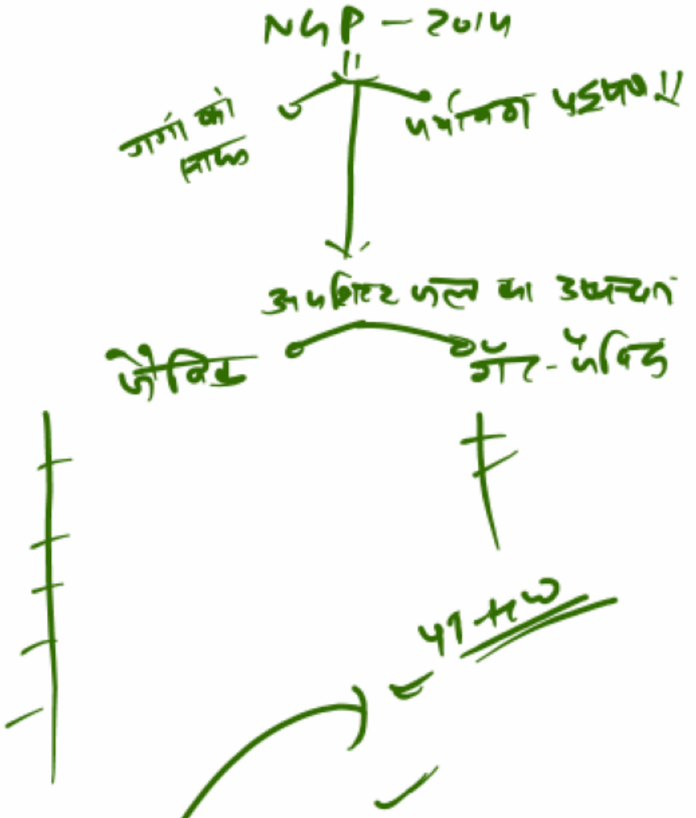
## प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न (Prelims MCQs)

**नमामि गंगे मिशन के तहत अपशिष्ट जल उपचार (Wastewater Treatment) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. अपशिष्ट जल के प्रभावी उपचार के लिए स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध अवसंरचना और जल की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है।
2. शहरी क्षेत्रों में जिन इलाकों में पूर्ण सीवर नेटवर्क नहीं है, वहाँ सेप्टिक टैंक और स्थानीय प्रणालियों के माध्यम से अपशिष्ट जल एकत्रित और उपचारित किया जाता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2



- **मुख्य परीक्षा के प्रश्न (Mains Questions)**

- "नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत अपशिष्ट जल उपचार में नवीन प्रौद्योगिकियों और नवाचार की भूमिका की विवेचना कीजिए। पारंपरिक प्रणालियों के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकियों का संयोजन किस प्रकार भारत में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बना सकता है?"

*(150 शब्द / 10 अंक)*

15 October 2026

Social Welfare

# प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

PM- NSAP

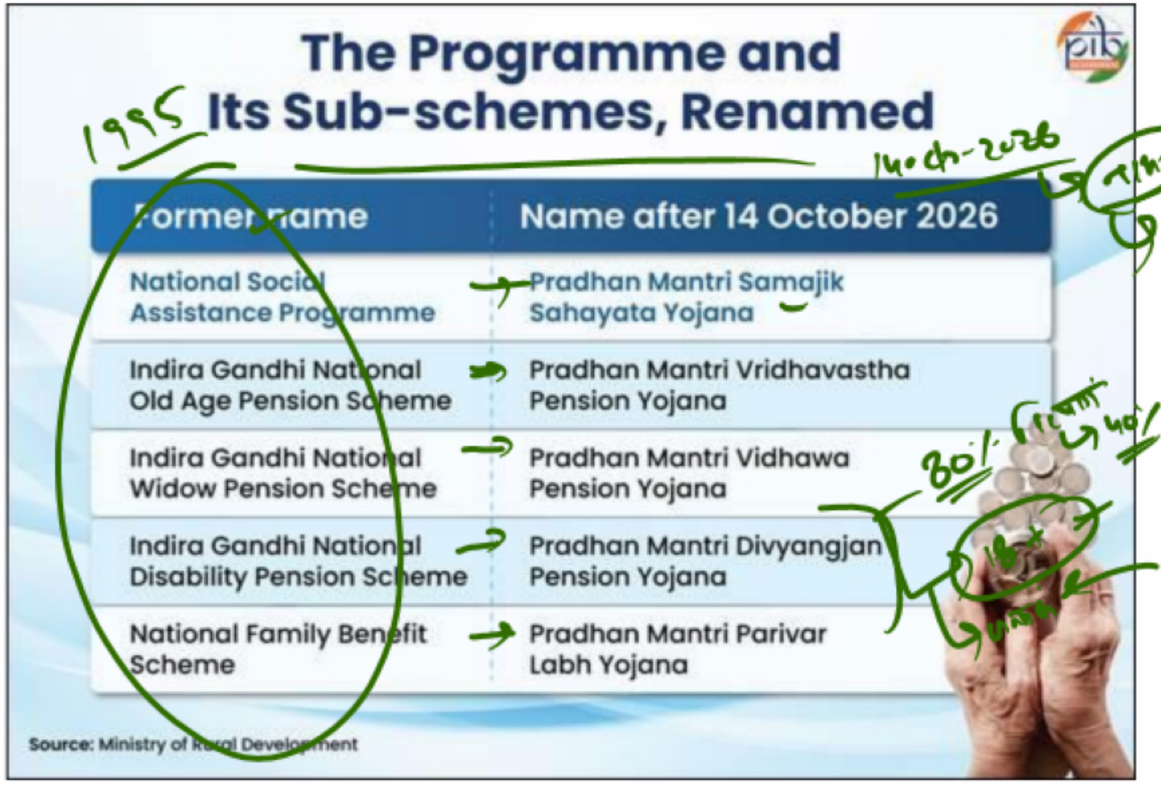
## सामाजिक सहायता के पांच और वर्ष, इसके दायरे में दिव्यांगजनों को व्यापक तौर पर शामिल किया गया

Posted On: 22 OCT 2026 2:20PM

*14* अक्टूबर *2026* को, केंद्रीय मंत्रिमंडल **ने *53,428* करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ, पांच वर्षों *(2026-27* से *2030-31)* के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जारी रखने की मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर **प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना** कर दिया गया है और इसकी चार उप-योजनाओं के नाम भी इसी के अनुसार बदल दिए गए हैं। जहां बुजुर्गों, विधवाओं और परिवार लाभ की पेंशन योजनाएं अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी, जबकि दिव्यांग पेंशन में संशोधन किया गया है। अब इसमें *80* प्रतिशत की जगह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम *2016* के तहत ***40* प्रतिशत** दिव्यांगता मानक का उपयोग किया जाएगा। इसकी ***18* वर्ष** की न्यूनतम आयु सीमा हटा दी गई है और अब जन्म से ही पात्रता लागू होगी। ***0-79* वर्ष** की आयु के लिए केंद्रीय सहायता बढ़कर ***375* रुपये प्रति माह** और ***80* वर्ष** तथा उससे अधिक आयु के लिए ***625* रुपये प्रति माह** हो गई है। इसके अलावा, दिव्यांग योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या ***8.33* लाख** से बढ़कर ***27.48* लाख** हो गई है।

## सामाजिक सहायता के लिए नवीकृत कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को ग्रामीण विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता का कार्यक्रम को पांच वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यह मंजूरी 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए है और इसमें **53,428 करोड़ रुपये** का वित्तीय परिव्यय शामिल है।
- यह स्वीकृति तीन विषयों से संबंधित है। इसमें कार्यक्रम और इसकी प्रत्येक उप-योजना का नाम बदलने, दिव्यांगजन पेंशन में संशोधन जबकि अन्य उप-योजनाओं को उनके मौजूदा स्वरूप में ही जारी रखा गया है।
- इस कार्यक्रम का नाम अब **प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना** है। इसके चारों पेंशन उप-योजनाओं के नए नाम इस प्रकार हैं: वृद्धावस्था पेंशन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया है; विधवा पेंशन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना किया गया है; दिव्यांगजन पेंशन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कर दिया गया है; और पारिवारिक लाभ योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना कर दिया गया है।




- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगे। जबकि विकलांगता पेंशन की पात्रता इसके दायरे और इसकी सहायता दर में बदलाव किया गया है।

## राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या है

- यह कार्यक्रम **15 अगस्त 1995** को आरंभ किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 41 को प्रभावी बनाता है, जो सरकार को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। यह एक पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित योजना है और इसमें **100 प्रतिशत** केंद्रीय सहायता मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को देश में कहीं भी कम से कम न्यूनतम सहायता अवश्य प्राप्त हो। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समाहित करता है, और इसके घटक बुनियादी शर्त यह है कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- इस कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक हैं। इसके तहत वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था है जबकि चौथा घटक परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर मिलने वाला एकमुश्त पारिवारिक लाभ है।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन योजनाओं को मुख्य रूप से अपने सामाजिक कल्याण विभागों के माध्यम से लागू करते हैं, और कई राज्यों में ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, राजस्व या श्रम विभागों के माध्यम से लागू किया जाता है। ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएं लाभार्थियों की पहचान करने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, और भुगतान मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा किया जाता है।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय दर के ऊपर सहायता में अपनी स्वयं की अतिरिक्त राशि भी जोड़ते हैं। सितंबर 2026 तक ये अतिरिक्त राशि प्रति लाभार्थी **50 रुपये से 5700 रुपये प्रति माह** के बीच थे, जिससे अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1100 रुपये की औसत मासिक पेंशन मिलती थी। इसलिए केंद्रीय दर वह आधार दर है जिस पर प्रत्येक राज्य सहायता राशि निर्धारण करते हैं।
- यह कार्यक्रम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए योजना-वार सीमाओं के मुकाबले लगभग **3.09 करोड़ लाभार्थियों** में व्याप्त रहा। इसके तहत 2025-26 के लिए 9,652 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें विकलांगता पेंशन 290 करोड़ रुपये रही। 14 अक्टूबर 2026 को मंजूरी मिलने के बाद इस कार्यक्रम का दायरा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.20 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच गया है।



## प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न (Prelims MCQs)

- **हाल ही में मंजूर की गई 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' (पूर्व में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. इसे आगामी 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) की अवधि के लिए ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
2. दिव्यांग पेंशन के तहत अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता मानक वाले व्यक्ति पात्र होंगे।
3. दिव्यांग योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है तथा जन्म से ही पात्रता लागू की गई है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3 सभी

## मुख्य परीक्षा के प्रश्न (Mains Questions)

- "हाल ही में पुनर्गठित 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' में दिव्यांगजनों के लिए किए गए संशोधनों का समावेशन की दिशा में क्या महत्व है? यह नीतिगत बदलाव भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को किस प्रकार बढ़ावा देगा?"

*(150 शब्द / 10 अंक)*

# महत्वपूर्ण तथ्य

# *Prasar Bharati is not a public service broadcaster*



**Suhas Borker**

Editor, Citizens First TV (CFTV), who has advocated public service broadcasting since the 1990s as convener of Jan Prasar. In 2000, he conceptualised National Public Service Broadcasting Day, on November 12

When the Narendra Modi government took office in May 2014, the then Information and Broadcasting Minister, Prakash Javadekar, promised to end the "government fiefdom" over Prasar Bharati and recast it on the British Broadcasting Corporation (BBC) model: autonomous in administration, free in editorial judgement, and accountable to Parliament.

Twelve years later that promise remains unfulfilled. The 138th episode of "Mann Ki Baat", broadcast on September 27, 2026, is only the most visible reminder that the state still treats the public airwaves as its own platform.

**The BBC model, unfulfilled**

The irony is sharp. The same political class that invoked the BBC as the template, later accused it of a "continuing colonial mindset" after it telecast the documentary in 2023, "India: The Modi Question". From April 2024 the BBC had to split its Indian news operation to meet foreign-investment rules.

The deeper story is older than the Emergency. In 1948, Jawaharlal Nehru told the Constituent Assembly – then the only authoritative Indian statement on the British model – "my own view of the set-up for broadcasting is that we should approximate, as far as possible, to the British model, the BBC, that is to say, it would be better if we had a semi-autonomous corporation under the government, of course with the policy controlled by the government, otherwise not conducted as a government department." Even that caveat – "otherwise not conducted as a government department" – has not been honoured.

Mark Tully, former BBC bureau chief in Delhi, put the same distinction succinctly in a conversation in 2017: public service broadcasting "is not the same as government broadcast". It rests on two principles, he said – that the government must not interfere in the broadcaster's autonomy, and that programmes must not be judged by commercial merit alone. Without autonomy and freedom, he added, All India Radio cannot become a broadcaster for transformative change.

The Emergency of 1975 reduced All India Radio (AIR) and Doordarshan to instruments of the regime. After Indira Gandhi's defeat, the Janata government asked B.G. Verghese to recommend autonomy. His BBC-style model became a Bill in 1979 (Prasar Bharati Bill), but the Bill lapsed. A new version, introduced in 1989 as "a charter of freedom" under Article 19(1)(a) of the Constitution, received assent in 1990 – as the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 – and was enforced only in 1997. Its Statement of Objects and Reasons said the corporation should be "a genuinely autonomous body – innovative, dynamic and flexible – with a high degree of credibility", responsible to the people and to Parliament. Nearly three decades on, Prasar Bharati is not that body. It is a pretender, a mouthpiece of the government of the day. Section 12 of the Act is the editorial constitution that was meant to lock that intent in. The primary duty is to organise public broadcasting services to inform, educate and entertain. Section 12(2)(b) requires the corporation to safeguard "the citizen's right to be informed freely, truthfully and objectively" and to present "a fair and balanced flow of information including contrasting views without advocating any opinion or ideology of its own".

Prasar Bharati remains a pretender — 12 years after a promise of BBC-style autonomy, the corporation is still on a ministerial leash

**At the Ministry's mercy**

A truncated corporation was set up so that it cannot function independently of government. Critical Sections 13, 14 and 15 of the Act remain unimplemented. Section 13 requires a 22-member parliamentary committee, elected from both Houses, to oversee Prasar Bharati on Parliament's behalf. No government has constituted it. Former chief executive Jawhar Sircar has explained why: Ministers insist that they alone are answerable to Parliament and therefore retain the power to summon AIR and Doordarshan officials until they succumb.

Sections 14 and 15 require a Broadcasting Council to receive complaints and guard political impartiality. That Council has never been set up, and it follows that there is no system for editorial redress. The Board, meant to be professionally managed, has been filled with pliable bureaucrats. Ownership of assets and staff was never transferred. Without its own fund, the Board remains at the Ministry's mercy. Section 23 still lets the Centre issue binding directions on what may or may not be broadcast.

Section 10 required a recruitment board to keep appointments free of government interference. Nothing happened until July 2020, when Jagadish Upasane, who headed Bharat Prakashan, publisher of Panchajanya and Organiser, was made chairman. Autonomy was compromised the moment it was announced. A 2021 manpower audit used the BBC as the benchmark: almost half of Prasar Bharati's then 25,000-strong workforce sat in engineering, against a little over 10% at the BBC, while content staff were under 20% against about 70%. The numbers described a transmission machine, not a Content-and-News-driven broadcaster.

UNESCO's 2001 definition is exacting. Public broadcasting is neither commercial nor state-controlled; it speaks to every citizen. Prasar Bharati fails that test. In 2000 the government declared November 12 as Public Service Broadcasting Day to mark Gandhiji's only AIR broadcast, made in 1947 to two lakh refugees at Kurukshetra. The day has since become tokenism. In 2022 even that tokenism turned into farce when a Christian hymn sung by school students was sought to be dropped from the commemorative national broadcast.

The social contract is simple. The broadcaster has the right to speak freely, and in return it owes the public accuracy, impartiality, and independence from both the market and the Ministry. Nehru's 1948 formula already drew that line: policy may be set, the daily conduct of broadcasting may not be run as a government department. In 1995, Justice P.B. Sawant, speaking for the Supreme Court in *Secretary, Ministry of Information and Broadcasting vs Cricket Association of Bengal*, went further. Airwaves are public property, he held, and the Centre must establish an independent autonomous public authority to control their use. Public broadcasting is not state broadcasting. That direction has still not been carried out.

**There must be political will**

What needs to be done is already known. The parliamentary committee must be constituted, the Board rebuilt as a professional body, and assets and staff transferred. The regulatory council named in the Act must be created, funding designed without government strings, and Indian Information Service officers removed from operational control. The 1990 Act must be amended where practice has exposed its traps.

None of this happens without political will. The syndrome is familiar: autonomy is criticised out of power and forgotten in power. In August 2026, the government told the Lok Sabha that it had received no formal complaints from journalists or media bodies about its autonomy in the previous year. The absence of filed grievances is not evidence of independence. The Broadcasting Council named in the Act was never created, so there is nowhere for such a complaint to go.

The Chanda Committee, appointed when Indira Gandhi was Information and Broadcasting Minister, concluded in 1966 that "a psychological transformation is necessary" in the government's approach to broadcasting. Sixty years later that transformation has not come, and Nehru's "otherwise not conducted as a government department" remains unkept words. The options before the people are two: approach the courts to enforce the Act and the Sawant direction, or wait for the 2029 general election and a Lok Sabha willing to turn Prasar Bharati from a government handmaiden into a public service broadcaster. Until then it remains what it has been for nearly three decades: a disguised pretender.

# महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रसार भारती की स्थापना **23 नवंबर 1997** को की गई थी (यह प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत बना है)।
- **मंत्रालय (Ministry):** प्रसार भारती **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** (Ministry of Information and Broadcasting, भारत सरकार) के अंतर्गत आता है।
- **सरकार का नियंत्रण (Government Control):** हालाँकि इसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) की तरह एक पूरी तरह से स्वायत्त (autonomous) निकाय बनाने का वादा किया गया था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इस पर सरकार का काफी नियंत्रण बना हुआ है:
  - इसके कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान (जैसे संसदीय समिति और ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल का गठन) आज तक लागू नहीं किए गए हैं।
  - वित्तीय स्वतंत्रता न होने और संपत्ति व कर्मचारियों का पूरा हस्तांतरण न होने के कारण यह आज भी मंत्रालय और सरकार पर निर्भर है।
  - अधिनियम की धारा 23 के तहत केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह क्या प्रसारित होगा या नहीं, इसके लिए निर्देश जारी कर सकती है।

## मुख्य बातें

- **अधूरी स्वायत्तता (Unfulfilled Autonomy):** 2014 में सरकार ने प्रसार भारती को BBC की तर्ज पर पूरी तरह स्वायत्त (autonomous) और स्वतंत्र बनाने का वादा किया था, लेकिन 12 साल बाद भी यह वादा अधूरा है। प्रसार भारती को वास्तव में स्वतंत्र बनाने के बजाय सरकार के मंच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
- **कानूनी प्रावधान लागू नहीं हुए:** प्रसार भारती अधिनियम 1990 की धारा 13, 14 और 15 को अब तक लागू नहीं किया गया है।
  - धारा 13 के तहत संसद की 22 सदस्यीय संसदीय समिति बननी थी, जो प्रसार भारती पर नज़र रखे।
  - धारा 14 और 15 के तहत 'ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल' बननी थी, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करे और शिकायतों का निवारण करे।
- **मंत्रालय पर निर्भरता:** भर्ती बोर्ड, वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति हस्तांतरण जैसे मामलों में सुधार न होने के कारण प्रसार भारती आज भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर निर्भर है।
- **सरकारी प्रसारण बनाम सार्वजनिक प्रसारण:** सार्वजनिक प्रसारण (Public Broadcasting) का मतलब सरकार का प्रचार करना नहीं होता, बल्कि नागरिकों को निष्पक्ष, सत्य और संतुलित जानकारी देना होता है। सर्वोच्च न्यायालय (1995 के सावंत फैसले) ने भी कहा था कि हवा/तरंगें (Airwaves) सार्वजनिक संपत्ति हैं और प्रसारण पर सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** चंदा समिति (1966) से लेकर अब तक कई सिफारिशें आईं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण प्रसार भारती को एक वास्तविक स्वतंत्र सार्वजनिक प्रसारक नहीं बनाया जा सका है।

# महत्वपूर्ण तथ्य

## *Thirukkural* to take centre stage at Kashi Tamil Sangamam

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

The fifth edition of the Kashi Tamil Sangamam, to be held from November 28 to December 12, will be built around the theme of the classical Tamil text, *Thirukkural*, Union Education Minister Pralhad Joshi said on Thursday.

Launching the registration portal for the event, Mr. Joshi said it would celebrate, reaffirm, and strengthen age-old civilizational bonds between Tamil Nadu and Kashi, two ancient seats of learning, according to an Education Ministry statement. This is in line with the spirit of unity exemplified in the government's slogan, *Ek Bharat Shreshtha Bharat* (One India, Great India).

Adopting the theme, *'Thirukkural Payilvom - Thirukkural Abhyas Karen'* (Let's learn *Thirukkural*), the event seeks to bring the ethical and moral wisdom of the Sangam-era *Thirukkural* to modern youth and learners, the statement said. "Through educational engagement, multilingual resources and wider public outreach, the programme seeks to encourage reading, understanding and application of universal values as enshrined in the text, in everyday life," it added.

As part of the programme, around 1,400 participants from Tamil Nadu, organised into seven groups of 200 each, will undertake an eight-day journey comprising four days of travel and four days of visits and structured programmes. The itinerary will include Varanasi, Prayagraj, and Ayodhya, featuring cultural, academic, domain-specific, and spiritual engagements, the Ministry said.

"The emphasis on youth participation will enable a new generation to engage meaningfully with India's classical knowledge traditions and carry their values into contemporary academic, professional and social life," it added.



Union Minister Pralhad Joshi during the launch of the registration portal for Kashi Tamil Sangamam on Thursday. ANI

Interested applicants may register through the official portal at https://kashitamil.iitm.ac.in/ hosted by the Indian Institute of Technology-Madras from Thursday till November 13.

Applications will be accepted under seven categories: students, teachers, writers and media professionals, agriculture and allied sectors, professionals and artisans, women, and spiritual leaders.

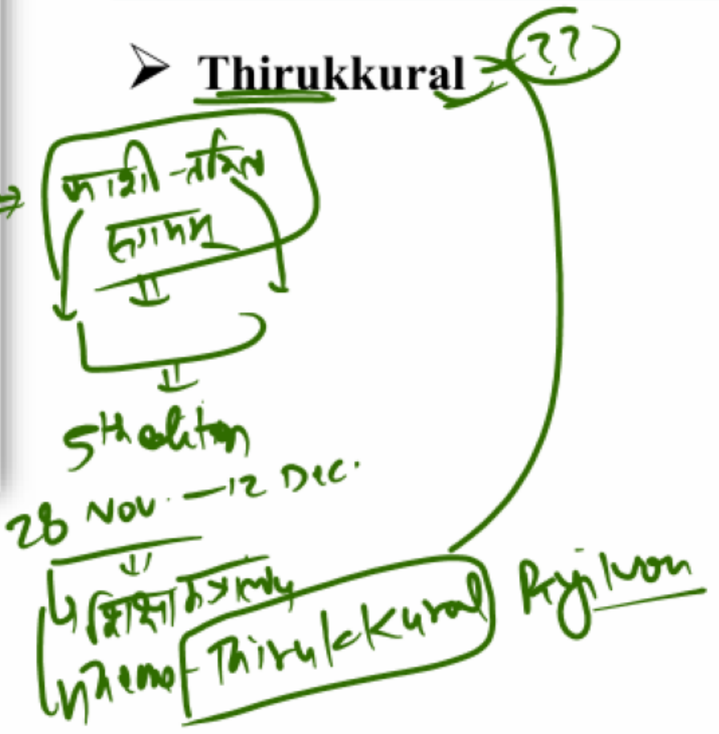
A nationwide students' engagement programme will be undertaken through 1,000 higher education institutions across the country to promote a wider understanding of the *Thirukkural* among students from diverse academic disciplines and linguistic backgrounds, the Ministry said. The initiative will include structured study, research, and campus-based activities for wider dissemination of the teachings and values of the *Thirukkural*. More details are available at www.kts.cict.in.

*Thirukkural* experts from Tamil Nadu will visit various schools and colleges in Varanasi and introduce the students to the core values of the text through orientation modules, interactive sessions, and quizzes. The National Book Trust, in association with the Rashtriya e-Pustakalaya, will conduct interactive sessions in schools in Varanasi on reading habits, storytelling and creative activities.

The Kashi Tamil Sangamam will also leverage technology to make the teachings of the *Thirukkural* accessible to a wider audience across India.

Speaking at the portal launch, Mr. Joshi said that since ancient times, the country has had strong cultural unity. He noted that many people visited Kashi and Rameswaram as part of their religious traditions, reflecting the deep-rooted cultural bonds between the northern and southern parts of India, the statement said.

## YouTube Homework



# महत्वपूर्ण तथ्य

SRT

## Is a sugar-rich diet while on antibiotics a threat to the gut microbiome?

**Recent research suggests that what we eat while taking antibiotics may determine just how badly our gut microbial ecosystem is disturbed; the emerging challenge for medicine is how to kill harmful bacteria while preserving the microbial communities that help keep the human body healthy**

Biju Dharmapalan

Antibiotics are among modern medicine's greatest lifesaving discoveries. They have transformed once-dangerous bacterial infections into treatable conditions and remain indispensable in cancer care, surgery, and infectious disease management. But antibiotics come with side effects – the primary being they do not always distinguish between harmful bacteria and the enormous community of beneficial microorganisms living inside our gut.

Recent research suggests that what we eat while taking antibiotics may determine just how badly this microbial ecosystem is disturbed. In particular, sugar-rich foods may worsen antibiotic-induced damage to the gut microbiome.

A study published in *Nature* examined the relationship between diet, antibiotics, and the gut microbiome in patients undergoing allogeneic haematopoietic cell transplantation. The researchers analysed an unusually detailed dataset – 9,419 meals consumed by 173 patients, alongside more than 1,000 stool samples from 158 patients.

Their findings point to an important question. Could the food we eat while taking antibiotics influence how quickly our microbial ecosystem recovers?



**Vibrant system:** The human intestine is home to trillions of microorganisms, constituting a vital ecology for digestion, metabolism, and immunological control. GETTY IMAGES

### The invisible ecosystem inside us

The human intestine is home to trillions of microorganisms.

The gut microbiota, comprising bacteria and other microorganisms, constitutes a vital ecology for digestion, metabolism, and immunological control. A population of 'good bacteria' alone, however, does not determine a healthy microbiome: other factors such as equilibrium, diversity, and the interrelations among myriad microbial species play a major role as well. When this ecological equilibrium is disrupted, it may result in dysbiosis, a condition characterised by reduced microbial diversity and the proliferation of a few other organisms.

Antibiotics are a major cause of such disruption. This is especially evident in patients undergoing intensive medical treatments such as blood or bone-marrow transplantation, where antibiotics may be combined with chemotherapy, radiation, and other interventions that further stress the intestinal ecosystem. The new study reveals that diet can become an important additional factor.

Studying diet and the microbiome is notoriously difficult. People eat different foods every day, and conventional dietary questionnaires often depend on memory. The researchers overcame some of these limitations by studying patients who were hospitalised for haematopoietic cell transplantation.

Because their meals could be recorded repeatedly and stool samples collected over time, the investigators could examine diet and microbiome changes almost day by day.

They recorded thousands of individual meals and classified foods into groups such as grains, vegetables, fruits, meats, milk, oils, and sweets. They then compared dietary intake with changes in the gut microbiome.

One pattern stood out. When broad-spectrum antibiotics were being used, higher consumption of sweets and sugars was associated with a sharper decline in microbial diversity.

The researchers estimated that for every additional 100 grams of sweets consumed following broad-spectrum antibiotic exposure, mean microbial diversity decreased by about 24% compared with samples without previous antibiotic exposure.

A separate analysis based on macronutrients similarly found an additional decrease of about 20.6% for every 100 grams of sugar. In other words, sugar appeared to act less like an independent villain and more like an amplifier of antibiotic-induced disruption.

The most intriguing finding involved *Enterococcus*, particularly *Enterococcus faecium*. Under normal conditions, the gastrointestinal tract harbours a diverse microbial consortium in which many organisms vie for resources and ecological niches. Many of these competitors can be killed or inhibited by antibiotics, allowing only more resistant or adaptable organisms to survive. *Enterococcus* is one such organism. It can become an important cause of antibiotic-resistant bloodstream infections and has been associated with adverse outcomes in patients undergoing haematopoietic cell transplantation. The study showed that higher sweet intake during antibiotic exposure was associated with increased *E. faecium* abundance.

The researchers also tested their hypothesis in mouse models. When mice were fed sucrose along with an antibiotic, the *Enterococci* population increased 16.3-fold on day three and 33.4-fold on day six, compared with antibiotic treatment without additional sucrose. In cultures with only sucrose, enterococcal levels did not increase. This indicates that sugar alone has no effect without antibiotics; the problem arises when antibiotics disturb the gut ecosystem.

The study also showed that this disturbance did not take place due to low fibre intake.

### Should we avoid sugar with antibiotics?

Not really. Though the study signals a warning, it does not provide concrete evidence that everyone taking antibiotics will experience the same effect. The human participants in the study were seriously ill patients undergoing intensive cancer treatment, not healthy adults taking a short course of antibiotics for a routine infection.

The researchers themselves point out several limitations. Almost all patients initially received prophylactic antibiotics, while broader-spectrum antibiotics were introduced when clinically indicated. The need for these antibiotics could itself reflect greater illness severity. Dietary information outside hospital-provided food was also incomplete, and treatment-related symptoms could influence what patients chose to eat.

Therefore, the findings should not be interpreted as a reason to discontinue medically necessary antibiotics – or to impose restrictive diets on vulnerable patients without medical supervision. Instead, they open an intriguing area for further research.

### Rethinking antibiotic prescriptions

When doctors prescribe an antibiotic, the prescription traditionally focuses on the drug: which antibiotic, what dose, and for how long. Emerging microbiome science suggests we may eventually need to think more broadly. Perhaps an antibiotic prescription could one day include advice on how to protect the microbial ecosystem during treatment.

The new *Nature* study suggests that temporarily reducing foods rich in simple sugars could be one possible strategy. But prospective clinical trials must demonstrate whether this actually improves patient outcomes. The authors explicitly call for such studies.

The larger lesson extends beyond sugar. Our gut is an ecosystem, not merely a digestive tube. Medicines, food, and microbes constantly interact within it. An antibiotic may be prescribed to eliminate an infection, but it inevitably changes the microbial environment in which thousands of other organisms live.

The emerging challenge for medicine is therefore not simply how to kill harmful bacteria, but how to do so while preserving the microbial communities that help keep us healthy. And sometimes, the difference may lie not only in the medicine we take – but also in what we put on our plate while taking it.

*(Dr.Biju Dharmapalan is an adjunct faculty member at the National Institute of Advanced Studies, IISc campus, Bengaluru, and dean, academic affairs, Garden City University, Bengaluru. bijudharmapalan@gmail.com)*

### THE GIST

The human intestine is home to trillions of microorganisms, constituting a vital ecology

Several factors such as equilibrium, diversity, and the interrelations among myriad microbial species play a major role in maintaining a healthy microbial ecosystem

When this ecological equilibrium is disrupted, it may result in dysbiosis, a condition characterised by reduced microbial diversity and the proliferation of a few other organisms

Antibiotics are a major cause of such disruption: this is especially evident in patients undergoing intensive medical treatments where antibiotics may be combined with other interventions that further stress the intestinal ecosystem

## YouTube Homework

- Dengue
- Malaria
- Rabies
- Sickle Cell Anaemia

- Antibiotics
- Dysbiosys

# महत्वपूर्ण तथ्य

# Chemical signatures could help detect diseases early, but accuracy and access remain challenges

Athira Elssa Johnson



Chemical signatures or biomarkers, are being studied to improve diagnosis of several diseases, particularly those affecting the brain and nervous system. GETTY IMAGES

Why does one person develop memory problems while another experiences seizures or changes in behaviour? And how do doctors find out whether these symptoms are caused by Alzheimer's disease, an immune disorder, or something else?

Sometimes, the answers may lie in tiny changes in the body's chemistry. Diseases can cause certain proteins and other molecules to appear in different amounts or behave differently. By measuring these changes, doctors can find clues as to what is happening inside the body, even when the cause is not immediately obvious.

These clues, called chemical signatures or biomarkers, are being studied to improve the diagnosis of several diseases, particularly those affecting the brain and nervous system.

The challenge is to establish what these changes mean, how reliably they point to a particular disease, and whether patients can access the tests.

## What are chemical signatures?

A chemical signature is a unique pattern of molecules, elements, isotopes, or by-products identified in a sample by analytical instruments such as spectrometers or chromatographs. "Chemical signatures are like the body's fingerprints," says Sreenivas U.M., consultant neurologist, Apollo Speciality Hospitals, Vanagaram, Chennai. When a disease develops, the balance of certain chemicals or proteins may change, providing clues to the problem, he adds.

In Alzheimer's disease, for instance, doctors and researchers look for changes in proteins called amyloid-beta and tau. Certain forms of these proteins can be measured in blood and cerebrospinal fluid, the liquid surrounding the brain and spinal cord. Tests measuring phosphorylated tau, particularly p-tau217, can help identify changes associated with Alzheimer's disease.

Researchers are also studying alpha-synuclein, a protein associated with Parkinson's disease. In another condition, autoimmune encephalitis, tests that detect antibodies directed against particular brain proteins can help identify an immune response affecting the brain.

This condition can cause seizures, memory problems and changes in behaviour.

## Detecting symptoms

Finding these changes also does not always mean an individual has, or is going to have a particular disease. The distinction is important: a test may identify changes associated with Alzheimer's disease, but doctors still need to consider the person's symptoms and overall health before deciding what those results mean.

Chemical signatures can also help distinguish conditions that appear similar. Autoimmune encephalitis, for example, may initially be mistaken for a psychiatric illness because it can cause behavioural changes and problems with memory. Identifying specific antibodies can help doctors recognise the condition and begin appropriate treatment. "In neurosurgery, examining the molecular characteristics of a brain tumour can help doctors classify it and decide on treatment," says Aqib M., senior consultant neurosurgeon, Dr. Mehta's Hospitals, Chennai. Selected molecular tests are already used in specialist practice. Researchers are also studying markers such as neurofilament light, a protein that can indicate damage to nerve cells, he adds. However, not every promising test is ready for routine use. Some markers indicate damage that can occur in several diseases rather than identifying one specific condition.

## Testing and diagnosis

A chemical signature cannot always give the full picture. Age, kidney function, medication and other illnesses can affect the levels of certain molecules. Doctors consider the patient's symptoms, medical history and examination findings, along with brain scans and other investigations when necessary.

Cost and availability pose further challenges in India. Specialised tests may not be offered at every hospital, and patients may have to travel to larger centres to access them. Differences in laboratory methods can also affect how consistently results are interpreted.

So, for patients, chemical signatures could mean clearer answers and shorter waits for a diagnosis. But their importance lies not just in detecting changes in the body, but in understanding what those changes mean.

(athira.elssa@thehindu.co.in)

# YouTube Homework

- Digital Signature
- ELISA Test

# महत्वपूर्ण तथ्य

## Chemical Signature (रासायनिक हस्ताक्षर) क्या है?

- **Chemical Signature** (जिसे रासायनिक फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है) किसी विशिष्ट पदार्थ, जीव, व्यक्ति या पर्यावरण में पाए जाने वाले रसायनों (Chemicals) का एक अनूठा पैटर्न या संयोजन होता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति के हाथों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, उसी प्रकार हर रासायनिक मिश्रण का एक अनूठा 'केमिकल सिग्नेचर' होता है, जिससे उसकी पहचान की जाती है।

## मेडिकल क्षेत्र (Medical Field) में इसका उपयोग

- स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में केमिकल सिग्नेचर का उपयोग बीमारियों की सटीक पहचान और इलाज के लिए व्यापक रूप से किया जाता है:
- **1. बीमारियों की शुरुआती पहचान (Early Disease Detection):**
  - कैंसर, डायबिटीज और लिवर की बीमारियों में शरीर के अंदर बायो-मार्केर्स (Bio-markers) बदल जाते हैं। इन केमिकल सिग्नेचर की पहचान करके बीमारी का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकता है।
- **2. सांस द्वारा जाँच (Breath Analysis):**
- इंसान की सांस में हजारों 'वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स' (VOCs) होते हैं। फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer) या टीबी (TB) जैसी बीमारियां होने पर सांस का केमिकल सिग्नेचर बदल जाता है, जिसे स्पेशल डिवाइस से डिटेक्ट किया जा सकता है।
- **3. सटीक/व्यक्तिगत इलाज (Personalized Medicine):**
- हर मरीज के शरीर में दवाओं के प्रति केमिकल रिस्पॉन्स अलग होता है। मरीज के रक्त या टिशू (ऊतक) के केमिकल सिग्नेचर का विश्लेषण करके उसके लिए सबसे प्रभावी दवा तय की जाती है।
- **4. फॉरेंसिक और दवा खोज (Drug Discovery & Forensics):**
- नई दवाओं के असर को जांचने और फॉरेंसिक मेडिकल जांच में शरीर में मौजूद जहर (Toxins) या किसी विशेष पदार्थ की पहचान करने के लिए केमिकल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है।

# महत्वपूर्ण तथ्य

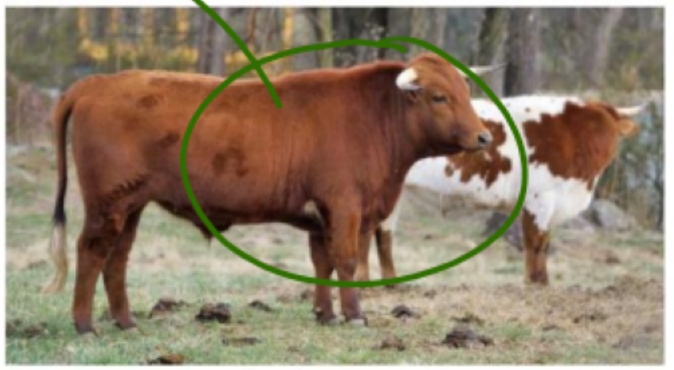
# France reports first human case of livestock virus Shamonda as man dies

**Reuters**
PARIS

France on Thursday reported the first human case of the Shamonda virus, usually found in livestock, in a patient who later died, with authorities adding there was no risk to the general population at this stage.

Transmitted by biting midges and most commonly found in cattle, Shamonda has also been found in horses, sheep and goats.

"The European Centre for Disease Prevention and Control is carefully monitoring the situation after the French authorities announced the first ever reported human infection with Shamonda virus, a disease that has until now only affected animals," the Stockholm-based ECDC said in a statement.



A representative image of cattle. GETTY IMAGES

"ECDC is in contact with the French authorities and European partners to investigate the potential public health implications," it said. "Investigations into whether the virus caused or contributed to the patient's death and how the infection was acquired are ongoing."

The French announcement said the leading hypothesis was that the patient was infected in eastern France, where the virus had circulated among animals this spring and summer.

# महत्वपूर्ण तथ्य

- **शामोण्डा वायरस (Shamonda Virus)** एक प्रकार का **आर्बोवायरस (Arbovirus)** है जो **बुन्याविरिडे (Bunyaviridae)** परिवार और **ऑर्थोबुन्यावायरस (Orthobunyavirus)** जीनस से संबंधित है।

- इस वायरस से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

**1. फैलाव और संचरण (Transmission)**

- **कैसे फैलता है:** यह वायरस मुख्य रूप से छोटे कीड़ों जैसे **मिडजिस (Culicoides)** और **मच्छरों** के काटने से फैलता है।
- **प्रभावित जीव:** यह मुख्य रूप से मवेशियों (Cattle), भेड़ों (Sheep) और बकरियों (Goats) जैसे पशुओं को प्रभावित करता है।

**2. लक्षण और प्रभाव (Symptoms & Impact)**

- **पशुओं पर असर:** वयस्कों में इसके लक्षण आमतौर पर बहुत हल्के होते हैं या कोई लक्षण दिखाई नहीं देता।
- **गर्भावस्था पर असर:** जब गर्भवती पशु इस वायरस से संक्रमित होते हैं, तो गर्भ में पल रहे बच्चे (भ्रूण) पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे जन्मजात विकार (Birth Defects) या गर्भपात (Abortion) की समस्या हो सकती है।
- **इंसानों पर असर:** इंसानों में इस वायरस से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी के आम मामले सामने नहीं आए हैं; यह मुख्य रूप से पशु चिकित्सा (Veterinary) से जुड़ा विषय है।

# महत्वपूर्ण तथ्य

# How significant is Alberta's referendum result?

Why is Alberta's separatist movement growing? Can Prime Minister Mark Carney contain it?

Vighnesh P. Venkitesh

**The story so far:**

The majority of citizens of the Canadian province of Alberta, in a referendum on October 19, chose to push down a rising separatist movement, giving Prime Minister Mark Carney much-needed relief and a boost amid tension with neighbouring U.S. over trade policies and President Donald Trump's provocative ambitions. While official results of the non-binding referendum are to be announced on October 29, the vote, with more than 97% of votes counted by October 21 morning, has given overwhelming support for the oil-rich province to stay with the country.

**Why is the province feeling separatist sentiments?**

Alberta, with its abundant 'oil sands', is home to the world's fourth-largest proven oil reserves, behind Venezuela, Saudi Arabia, and Iran. While neither the largest nor the most populous province in the North American country, Alberta accounts for more than 80% of Canada's crude oil production and contributes a disproportionate share to the country's economy among the provinces. This has long kept separatist sentiments alive along the fringes of the province's social fabric, with some believing that the province is not getting the same from the federal government as it is providing.

The environmentally friendly policies of liberal governments at the centre that aimed at putting curbs on oil extraction stoked the sentiments of the constituents of the conservationist province, which snowballed into a popular movement in recent years, helped along with resentment towards restrictions and regulations during the pandemic and post-pandemic period.

The MAGA movement under Mr. Trump on the other side of the border also inspired conservatives in the province, who rallied towards secession and autonomy which would let Alberta decide what to do with the oil present in its territory, and collect and keep the income from oil for itself.

**What did the latest referendum seek to settle?**

The referendum was initially introduced as a pair of motions approved in March with 9 questions on immigration and welfare policies and constitutional questions on federal structure and inter-provincial cooperation. The 10th question, added to the 9 initial ones with a separate order approved in May, dealt with the separation. Instead of seeking yes or no answers like the previous 9 questions, the last question gave voters two options.

Option one was that Alberta should remain a Province of Canada, while the second option called for the provincial government to commence the legal process to hold a binding referendum on whether or not Alberta should separate from Canada. In essence, the referendum wanted citizens of the province to either close the door on separation talks or urge the government to initiate a second referendum to decide on separation. With results from more than 97% of the voting centres, 15,44,284 votes out of a total of 20,60,524 counted, nearly 75% supported option one.

**How have leaders reacted?**

The votes against any separation referendum were a "large majority for Canada", Mr. Carney, who hails from Alberta, said after the unofficial results.

Alberta Premier Danielle Smith, who called for the vote in a sign of growing pressures from within her United Conservative Party, reacted to the early results as a vote for a "stronger Alberta in a united Canada".

However, separatist leaders have not given up. "We are not going anywhere", Jeff Rath, leader of the Alberta Prosperity Project and one of the faces of the separatist movement, said after the referendum results became apparent. Mr. Rath sees a silver lining in the 30% of votes for his cause. Former Premier Jason Kennedy had pointed out before the referendum that separatist parties traditionally attracted less than 2% of votes in elections and referendums. The 30% vote on October 19 is an exponential growth for the movement and could be the way to the mainstream for Mr. Rath and his ideas, one of which is replacing Ms. Smith as the head of the UCP and getting a pro-separatist government for the province, which takes forward.

But with global uncertainties and trade wars with the U.S. under Mr. Trump who had demeaned Canada's sovereignty multiple times with public comments about making the country a 51st State of the U.S., Mr. Carney needs his country united and resources flowing. He would also find strength from the fact that leaders of the separatist movement had public meetings with U.S. lawmakers in the run up to the referendum and yet he had the overwhelming solidarity from his home province.

The support from the referendum will boost his ambitions to get a major pipeline out of Alberta that he hopes could revive the economy. As an economist who was in charge of the Bank of England during Brexit, not having to go through the economic fallout from the separation of one of the most profitable provinces in the country would be a relief.

# महत्वपूर्ण तथ्य

## अल्बर्टा (कनाडा) के जनमत संग्रह (Referendum) का सार

- **परिणाम (Result):** कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 19 अक्टूबर को हुए जनमत संग्रह में लगभग **75% लोगों ने कनाडा के साथ बने रहने के पक्ष में वोट दिया**, जिससे अलगाववादी (Separatist) प्रस्ताव खारिज हो गया।
- **पीएम मार्क कार्नी को राहत:** इस नतीजे से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बड़ी राजनीतिक राहत मिली है।
- **अलगाववाद का कारण:** अल्बर्टा कनाडा के 80% से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है। वहाँ के लोगों में असंतोष था कि केंद्र सरकार की पर्यावरण नीतियों और तेल निष्कर्षण (Oil Extraction) पर पाबंदियों के कारण प्रांत को उसकी क्षमता के अनुसार लाभ नहीं मिल रहा है।
- **डोनाल्ड ट्रंप और MAGA का प्रभाव:** अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के MAGA आंदोलन ने भी अल्बर्टा के रूढ़िवादी नेताओं को स्वायत्तता और अपने संसाधनों पर खुद अधिकार जमाने के लिए प्रेरित किया।
- **अलगाववादी नेताओं का रुख:** जनमत संग्रह में हार के बावजूद अलगाववादी नेता जेफ राथ (Jeff Rath) का मानना है कि मिले 30% वोट इस आंदोलन की बड़ी बढ़त को दर्शाते हैं और वे अपना प्रयास जारी रखेंगे।



# महत्वपूर्ण तथ्य

## Tied by geography, divided by politics

With speculation rife that Bangladesh's recently elected Prime Minister Tarique Rahman (and also Bangladesh Nationalist Party (BNP) Chairman) will be visiting New Delhi in November or December, it is time to assess the state of India-Bangladesh relations and analyse the roots of the problems between the two countries.

The seeds of their current tension lie in the liberation war of 1971 itself. From the very beginning, the attitude of Bangladesh's elites toward India has wavered between gratitude and resentment – gratitude for India's crucial role in the liberation of their country and resentment against the fact that India had to play the role of liberator – a role they should have performed themselves.

### An ambivalence

Nations cherish narratives in which they are the principal authors of their own liberation. Bangladesh is no exception. The contribution of the Mukti Bahini notwithstanding, the decisive military blow against Pakistan was delivered by India. What was initially the source of immense gratitude with the passage of time became a source of grave discomfort.

Moreover, from the very beginning Dhaka was worried that India's policy towards Bangladesh would be mediated through a Hindu-majority West Bengal next door which has strong cultural and linguistic affinities with Bangladesh that could threaten the development of Bangladesh's independent identity. The open borders in the immediate aftermath of the liberation war also revived memories of the socio-economic dominance of the Hindu bhadralok in pre-Partition Bengal.

This was compounded by the fact that Bangladesh was virtually surrounded by India, sharing a border of more than 4,000 kilometres. Its principal rivers flowed through or originated in India. Its economic and strategic room for manoeuvre appeared constrained by geography. Consequently, the fear of Indian domination became an important component of Bangladeshi nationalism.



**Mohammed Ayoob**

University Distinguished Professor Emeritus of International Relations, Michigan State University, and the author, with K. Subrahmanyam, of 'The Liberation War' (1972)

India and Bangladesh must overcome mistrust and pursue pragmatic neighbourhood cooperation

The honeymoon between Dhaka and New Delhi was indeed short. Sheikh Mujib and Indira Gandhi shared a great deal of goodwill. But the governments that succeeded Mujib deliberately distanced Bangladesh from India. Under Ziaur Rahman, Bangladeshi nationalism was redefined in overtly Islamic terms in contradistinction to the linguistic nationalism that had provided the ideological foundation of the liberation movement.

### Dhaka's foreign policy

This had important foreign policy consequences. Dhaka sought closer relations with Pakistan, China, and the United States to counterbalance India. What New Delhi often interpreted as gratuitous anti-Indianism was, from Dhaka's perspective, an assertion of strategic autonomy by a much weaker state living in the shadow of an overwhelmingly powerful neighbour.

This pattern became deeply embedded in Bangladesh's domestic politics. The Awami League remained identified with the secular and Bengali-nationalist legacy of 1971 and generally favoured close relations with India. The BNP and its allies were much more suspicious of New Delhi. India consequently ceased to be merely a foreign policy issue; attitudes towards India became part of the contest over Bangladesh's national identity.

But this success contained the seeds of the subsequent backlash. India increasingly identified its interests not merely with Bangladesh but with Sheikh Hasina and the Awami League. As criticism mounted within Bangladesh over the increasingly authoritarian character of her government, New Delhi was widely perceived as placing its own security interests above Bangladesh's democratic evolution.

Ms. Hasina's overthrow in August 2024 therefore produced not merely a change of government but a profound crisis for Indian policy. Her flight to India reinforced suspicions that New Delhi was the external pillar of the political order just overthrown. India's continuing refusal to extradite her has ensured that the Hasina question remains a major bilateral irritant.

### The road ahead

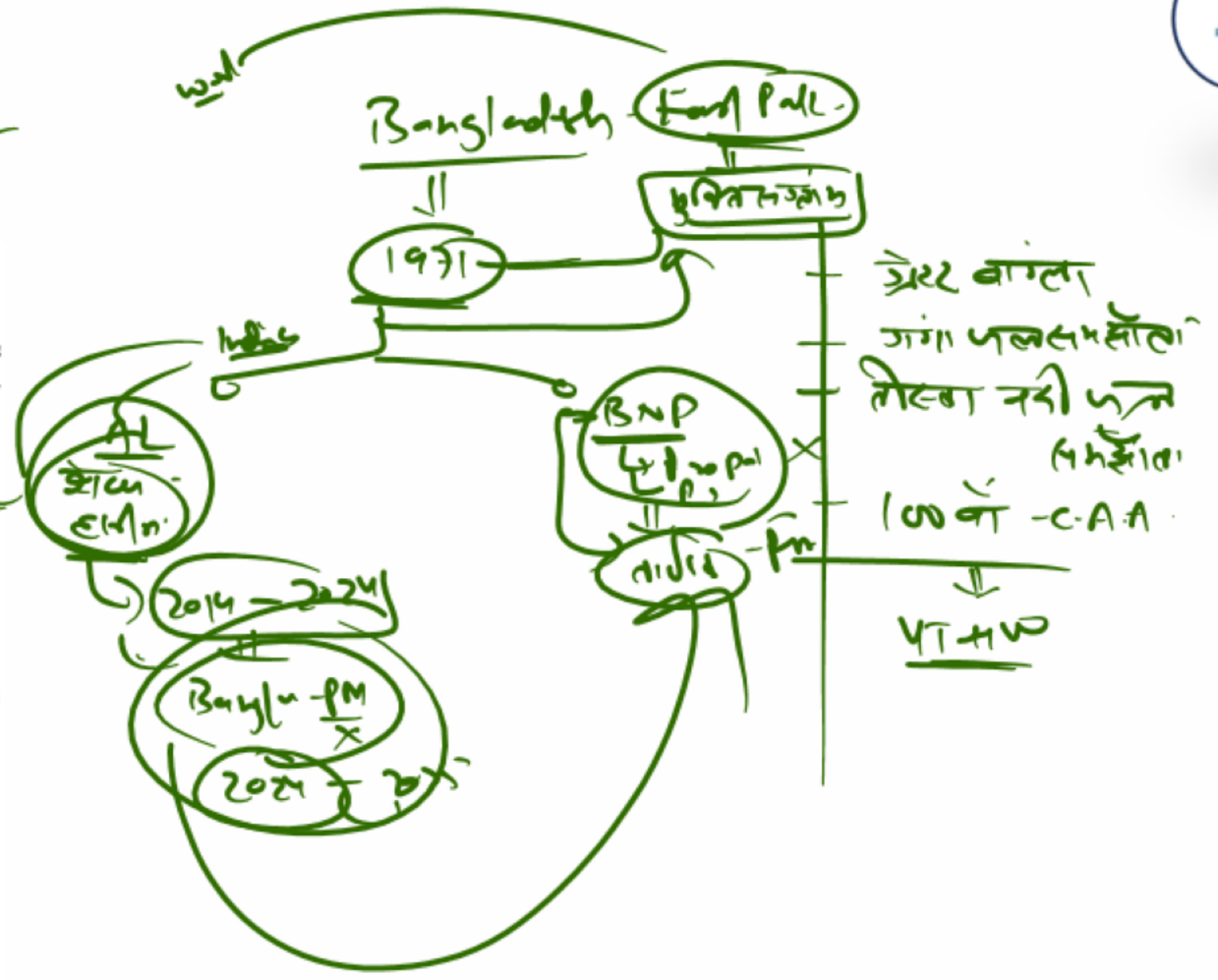
The election of Mr. Rahman and the return of the BNP to power in February 2026 have opened a new chapter. Both New Delhi and Dhaka have compelling reasons to avoid permanent alienation, and functional engagement has resumed. But substantial mutual suspicion continues to bedevil bilateral relations.

The lesson that New Delhi should draw from the turbulent history of the relationship is that India cannot expect gratitude for 1971 to constitute the permanent foundation of Bangladeshi foreign policy. Gratitude is a transient sentiment; national interest especially when linked to issues of national identity is enduring.

Indeed, repeatedly invoking India's role in Bangladesh's liberation can be counterproductive because it reinforces precisely the Bangladeshi psychological trauma that has troubled the relationship from its inception.

Dhaka, for its part, cannot wish away geography. No relationship with Beijing, Islamabad or Washington can substitute for a workable relationship with the country that surrounds Bangladesh on three sides, shares its major river systems and is indispensable to its regional connectivity.

India must learn to exercise its preponderant power with restraint and sensitivity and abjure demanding reciprocity for any magnanimity it shows towards its smaller neighbour especially on the sharing of river waters. Bangladesh must recognise that strategic autonomy need not be defined through knee-jerk opposition to India. Only then can the two countries finally move beyond the burdens of the past while preserving its most important legacy: the recognition that their security and stability are inextricably intertwined.



# महत्वपूर्ण तथ्य

- **ऐतिहासिक द्वंद्व (Historical Ambivalence):** 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की अहम भूमिका के लिए बांग्लादेश में आभार का भाव तो रहा, लेकिन साथ ही एक तरह का असंतोष भी रहा कि वे स्वयं अपनी मुक्ति के मुख्य सूत्रधार नहीं बन सके।
- **भूगोल और वर्चस्व का डर:** बांग्लादेश भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है (4,000 किमी से अधिक सीमा) और उसकी प्रमुख नदियाँ भारत से होकर आती हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ढाका में हमेशा भारत के वर्चस्व (Indian domination) का डर बना रहा।
- **विदेश नीति में संतुलन (Foreign Policy Balance):** भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने अक्सर भारत-विरोधी माना, जबकि ढाका के लिए यह उसकी रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) का हिस्सा था।
- **शेख हसीना और भारत पर असर:** भारत का झुकाव मुख्य रूप से अवामी लीग और शेख हसीना की सरकार की ओर रहा। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद उन्हें भारत में शरण मिलने से दोनों देशों के संबंधों में तनाव और अविश्वास बढ़ा है।

- **आगे की राह :**
- **भारत के लिए:** भारत को यह समझना होगा कि 1971 की कृतज्ञता (gratitude) हमेशा के लिए विदेशी नीति का आधार नहीं हो सकती। भारत को संयम, संवेदनशीलता और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- **बांग्लादेश के लिए:** ढाका को यह स्वीकार करना होगा कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता; चीन या अमेरिका के साथ संबंध भारत के साथ व्यावहारिक और क्रियात्मक संबंधों का विकल्प नहीं बन सकते।

# महत्वपूर्ण तथ्य

# Modi and Tusk discuss trade ties, India's plan to ease impact of Ukraine war

**Suhasini Haidar**
NEW DELHI

India and Poland have no "conflicts of interest", said Polish Prime Minister Donald Tusk, who hailed his Indian counterpart Narendra Modi as a "beacon of hope" in a time of "political uncertainty and instability" after talks here on Thursday.

Mr. Tusk, who is visiting as Prime Minister for the first time since 2010, discussed expanding India-Poland cooperation in a number of fields including space, transportation, renewable energy and technology, and also spoke about India's "four-point proposal" to help mitigate the effects of the Russia-Ukraine conflict.

While the two sides did not sign any agreement, India and Poland targeted doubling trade between them from a low figure of $6 billion, which is expected to rise after the India-European Union Free Trade Agreement is signed in December. "We are confident that companies from both countries will work together to develop trusted supply chains for the world and achieve our shared goal of doubling bilateral trade by 2030," said Mr. Modi.

The Prime Minister added he was pleased that a large business delegation had accompanied Mr. Tusk, to engage with Indian businesses in Delhi and Bengaluru on collaborations in areas such as rail transport, clean coal, and mining, where Poland has developed its technology.

Mr. Modi congratulated Poland for entering the group of nations with trillion-dollar GDPs.



**Steadfast partnership:** Prime Minister Narendra Modi with Polish PM Donald Tusk in New Delhi on Thursday. SUSHIL KUMAR VERMA

Mr. Tusk expressed his support for India's candidature for the United Nations Security Council's non-permanent seat for 2028-29 and for a permanent seat in a reformed UNSC, and hoped for Indian support for Poland's ambitions to join the G-20. U.S. President Donald Trump has invited Mr. Tusk to the G-20 this year in Florida, where Poland is expected to submit its request.

## Four-point proposal

India has not publicly shared details of a four-point proposal that the Modi government is discussing with counterparts in Moscow and Kyiv, with a view to forge an agreement between Russia and Ukraine that would stop attacks on civilians, allow grain and energy exports from both countries through the Black Sea, and end the targeting of ships and seafarers, including many Indians who have been casualties in the four-and-a-half year war.

Highly placed officials denied that India is "mediating" in the conflict, but said it is in close contact with both sides over the specific proposal.

India and Poland also announced a "Defence Industry" dialogue for cooperation in security, technology and hardware. However, no specific defence deals will be signed between the countries until they sign an Agreement on Mutual Protection and Exchange of Classified Information, which is still under negotiation, and could not be completed in time for the visit, officials said.

The deal will specifically seek to allay Poland's concerns about technology leaks to Russia given the India-Russia defence partnership, and India's sensitivities on the Poland's defence relationship with Pakistan.

PM SPEAKS TO NETANYAHU
» PAGE 6

# महत्वपूर्ण तथ्य

**YouTube Homework**

पश्चिम एशिया
West Asia

# Indian among 2 dead as Houthis target Saudi's Dammam airport

Attack on King Fahd International Airport injures eight, says the kingdom; Saudi forces targeted yacht carrying 14 Indians in Red Sea, and rescue operations are under way, say rebels; there will be siege for siege and escalation for escalation, they add

Stanly Johny

Two people, including an Indian national, were killed and eight injured on Wednesday in a Houthi attack on King Fahd International Airport in Dammam, Saudi Arabia's eastern oil hub, the kingdom's General Authority of Civil Aviation said.

The Iran-aligned rebels also claimed that Saudi Arabian forces on Thursday targeted an Indian yacht near Zuqar Island in Red Sea, carrying 14 Indians, adding that they were conducting rescue operations.

The Indian Embassy in Riyadh confirmed the Indian national's death. "Saudi authorities have informed that one Indian national was among two people who unfortunately lost their lives in the attack on Dammam airport yesterday night and two Indian nationals were injured," the embassy wrote in a social media post on Thursday. On Thursday, the Houthis (Ansar Allah) said they will continue their operations against Saudi Arabia. "There will be siege for siege and escalation for escalation," they said, adding the strikes would continue until Saudi Arabia lifts its blockade of the Houthi-held areas of Yemen.

If Saudi Arabia continues to attack Yemen, "we will resort to major options we did not want to take, and we hold it responsible for the consequences," the Iran-backed militants said, as per the Houthi-aligned Almasirah television.



**On watch:** Saudi Arabia-backed govt. troops seen in the Yemeni city of Taiz on Wednesday amid the conflict with the Houthis. AFP

**'Serious concerns'**

The targeting of a civilian vessel carrying Indian nationals raises serious concerns about the safety of international navigation and the potential for civilian casualties, the Yemeni militia said. "The [Houthi] Armed Forces are carrying out rescue operations for those on board, with further details to be provided later," they said, according to Almasirah television.

The Indian Embassy in Yemen responded to the reports on attack on the yacht. "We are ascertaining further details about the incident and will provide all possible help for ensuring the safety and well-being of the Indian nationals," it said on X.

The Houthis, who captured Sana'a in 2014 and expanded their territorial control along Yemen's entire Red Sea coast last month, said they launched missile and drone attacks at Saudi Arabia's Ministry of Defence in Riyadh and the Dammam airport. They also struck a facility of Aramco, the state-owned petroleum and natural gas company, in Yanbu, and Abha International Airport in the southwest.

Saudi Arabia started bombing Yemen in 2015 after the Houthis captured Sana'a a few months earlier. In 2022, Riyadh and the Houthi leadership agreed to a ceasefire as part of a broader Iran-Saudi rapprochement. The ceasefire collapsed in July, in the midst of the U.S.-Iran war, as the Sana'a airport was bombed by Saudi Arabia to prevent an Iranian airline carrying a Houthi delegation from landing.

In recent weeks, the Houthis have stepped up attacks against Saudi airports and energy infrastructure, while the kingdom has intensified its air strikes on the Houthi-controlled parts of Yemen.

## Efforts on to bring back thousands of stranded Indians

NEW DELHI

Amid escalating attacks on Saudi Arabia by the Iran-backed Houthi rebels, Indian missions in Riyadh and Jeddah are working with stakeholders to facilitate the early return of thousands of stranded pilgrims, the External Affairs Ministry said on Thursday. ▷ PAGE 4



# महत्वपूर्ण तथ्य

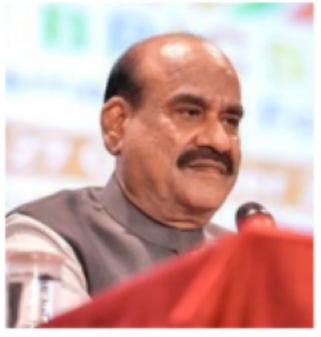
# BRICS Parliamentary Forum to meet in Delhi: Om Birla

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

A two-day conference of the 12th BRICS Parliamentary Forum will be held in New Delhi on October 26 and 27, with discussions centred on "Fostering parliaments for people-centric development", Lok Sabha Speaker Om Birla said at a press conference on Thursday.

"The two-day conference will include both bilateral and multilateral discussions. Presiding officers, members of Parliament and other dignitaries from BRICS and partner countries will brainstorm on strategic priorities for Parliaments," he said.

Prime Minister Narendra Modi will also attend the event, though no separate invitations were extended to Opposition leaders of the two Houses. India had received confirmation from most participating countries, though Saudi Arabia and Ethiopia expressed their inability to participate.


Om Birla

The deliberations will cover "institutional resilience, ethical artificial intelligence, digital transformation, reform of global governance and sustainable development".

Meanwhile, the Speaker avoided all questions regarding the delay in proroguing the Monsoon Session of Parliament and speculation about a special sitting to deliberate on delimitation legislation.

"Article 85 of the Constitution clearly says that the Speaker has no role in calling or proroguing a session. If I had a role, then I would have given a judgment," he said.

**Trinamool case**

Regarding the disqualification of 20 MPs who broke away from the original Trinamool Congress (TMC) in West Bnegal, Mr. Birla said he would expedite the process once the lawmakers submitted their responses. "Just like the Supreme Court is hearing the case, my court is also hearing the case, I cannot pass the judgment here," the Speaker said.

2026 - India
BRICS - शिखर सम्मेलन → youtube -
12th BRICS Parliamentary Forum
ससदीय फोरम - अध्यक्ष
26-27 october-2026
Fostering Parliaments for People-centric De.

# महत्वपूर्ण तथ्य

# In Instagram debut, Sonia Gandhi shares first glimpse of her memoir

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi made her Instagram debut on Thursday by sharing a video of her upcoming memoir, *Belonging: A Journey of Love*, which she described as a "story of love, duty, loss and finding a place to belong".

The former Congress president has largely stayed away from social media, using the party's official X handle to release video statements, letters and other messages.

In the first post on her Instagram account, Ms. Gandhi shared a video of herself receiving copies of the book and sharing sweets with Priyanka Gandhi Vadra and remarked that the book contained several photographs. "Hello everyone, I'm truly grateful to share this moment with you all; the first look of *Belonging: A Journey of Love*. It is a story of love, duty, loss and finding a place to belong. I look forward to sharing it with you," she said in her post.



**Pages of resilience:** Sonia Gandhi's memoir traces personal loss, family tragedies and moments in her political life. PTI

Congress communications chief Jairam Ramesh, sharing the video, said the "long-awaited memoir" of Ms. Gandhi would be released on November 10.

**Publishing controversy**

Last month, HarperCollins India announced that it would publish the memoir, ending uncertainty over its domestic release after an impasse between Ms. Gandhi's representatives and Penguin Random House India (PRHI).

The disagreement had triggered a controversy, with some Congress leaders alleging that pressure had been exerted on the publisher to remove references to Prime Minister Narendra Modi, the Rashtriya Swayamsevak Sangh and China's alleged occupation of Indian territory.

PRHI denied any external pressure and declined to disclose details, citing confidentiality obligations.

The memoir begins with Ms. Gandhi's childhood in post-war Veneto, Italy, and recounts her move to Cambridge, where she met Rajiv Gandhi in 1965. It traces her marriage to him, her introduction to her mother-in-law, former Prime Minister Indira Gandhi, and her efforts to adapt to life in India.

The book also recounts the tragedies that marked the family, including Sanjay Gandhi's death in a plane crash, Indira Gandhi's assassination in 1984 and Rajiv Gandhi's assassination in 1991. The book covers the Congress-led alliance's victory in the 2004 general election, Ms. Gandhi's decision not to become Prime Minister, and her leadership of the party and the ruling coalition during the subsequent decade.

→ Sonia Gandhi # Belonging :- A Journey of Love

# महत्वपूर्ण तथ्य

राष्ट्रपति सचिवालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

## भारत की राष्ट्रपति रायपुर में नुआखाई महोत्सव के अवसर पर आयोजित 'सेवा सम्मान पर्व' और 'युवा प्रबोधन' कार्यक्रम में शामिल हुईं

**अन्न का सम्मान करना, किसानों के योगदान को स्वीकार करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हम सब का सामूहिक दायित्व है: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु**

प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2026 6:21PM by PIB Delhi

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज 22 अक्तूबर, 2026 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में नुआखाई महोत्सव के अवसर पर आयोजित 'सेवा सम्मान पर्व' और 'युवा प्रबोधन' कार्यक्रम में शामिल हुईं।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि नुआखाई मिलन समारोह केवल एक सांस्कृतिक समारोह नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध परंपराओं, आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का उत्सव है। ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने, और भारतीय जीवन-मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं।

# महत्वपूर्ण तथ्य

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

## एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026

### दूसरे दिन की मुख्य बातें: राज्य नेतृत्व, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और मिश्रित वित्तपोषण तंत्र

प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2026 7:26PM by PIB Delhi

एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026 के दूसरे दिन राज्य स्तर पर नीतिगत नेतृत्व, तकनीकी नवाचार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और जलवायु वित्तपोषण समाधानों के क्षेत्रों में विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग और संवाद को गति मिली।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट(आईआईएसडी) और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र में ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के ऊर्जा एवं कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। इस सत्र में एग्रीवोल्टाइक के विस्तार में तेजी लाने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों को प्रस्तुत किया गया। इस सत्र में राज्यों को निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इसमें भूमि उपयोग के अभिनव मॉडलों, राज्य स्तर पर टैरिफ प्रोत्साहनों तथा स्थानीय कृषि परिस्थितियों और फसल विविधता के अनुरूप पीएम-कुसुम योजना को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि एग्रीवोल्टाइक में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में राज्य एवं उप-राष्ट्रीय स्तर की सरकारों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

**7वें 'एग्रीवोल्टिक्स विश्व सम्मेलन 2026'** (AgriVoltaics World Conference 2026) का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन से जुड़ी मुख्य जानकारी इस प्रकार है:

- **आयोजक:** इसका आयोजन भारत सरकार के **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** द्वारा जर्मनी के पर्यावरण, जलवायु कार्रवाई, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय (BMUV) के सहयोग और 'कोनेक्सियो-पीएसई' (Conexio-PSE) के साथ मिलकर किया जा रहा है।
- **स्थान:** यह सम्मेलन नई दिल्ली के **भारत मंडपम** में आयोजित हो रहा है।
- **अवधि:** यह एक **3 दिवसीय (तीन दिन)** सम्मेलन है, जिसका शुभारंभ 21 अक्टूबर 2026 को हुआ था और इसका समापन 23 अक्टूबर 2026 को हो रहा है।
- **विषय (Theme):** इस वर्ष के सम्मेलन की थीम "Powering the Global South" (ग्लोबल साउथ को ऊर्जा प्रदान करना) है। Facebook +3

# महत्वपूर्ण तथ्य

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

## पीएम दक्ष योजना के तहत 2020-21 से 2023-24 के दौरान 1,87,305 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 96,162 को रोजगार दिलाया गया

### 2024-25 से, पीएम दक्ष का एमएसडीई की पीएमकेवीवाई योजना में विलय कर दिया गया है

### मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, 90% से अधिक लाभार्थियों ने पाया कि उनका प्रशिक्षण उनके करियर लक्ष्यों और स्थानीय श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप था

प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2026 7:29PM by PIB Delhi

'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही' (पीएम दक्ष) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे 2020-21 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस), गैर-अधिसूचित जनजातियों (डीएनटी) और सफाई कर्मचारियों (जिसमें कचरा बीनने वाले भी शामिल हैं) को कौशल प्रशिक्षण देना है। यह प्रशिक्षण सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दिया जाता है, ताकि इन लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन्हें स्वरोजगार और वेतन-आधारित रोजगार पाने में मदद मिल सके।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) के तीन निगमों द्वारा लागू किया गया था। ये निगम हैं: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेडीसी)।

# Home Assignment

- ❑ World Day of War Orphans
- ❑ BRICS Summit

**प्रश्न:**

- **हाल ही में चर्चा में रहा "SANAA" निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, जिसे एक नए आर्थिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है?**

A. सऊदी अरब
B. यमन
C. संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
D. ओमान

# Thanks For Watching

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

## Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS

Small
Steps
Big
Results